तिब्बत देश

# तिब्बती रेल पर सवार चीनी उपनिवेशवाद

पिछले साल तिब्बत में गोरमो से ल्हासा तक अपनी रेलगाड़ी शुरू करने पर चीनी शासकों ने बड़े जोर शोर के साथ दुनिया के सामने दावा किया था कि इतना भारी खर्चा करने के पीछे उनका एकमात्र इरादा तिब्बत की जनता के विकास के लिए नए रास्ते खोलना है। चीनी नेता पिछले कई दशक से यह कहते आए हैं कि तिब्बत के पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए वहां रेलमार्ग बनाए बिना बात नहीं बनेगी। लेकिन हर बार बात इस बिंदु पर आकर रुक जाती थी कि तिब्बत की जनसंख्या इतनी कम है कि वहां के लिए रेल व्यवस्था का विकास करना व्यापारिक दृष्टि से घाटे का सौदा होगा।

1996 से 2000 की अपनी नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनायी गई बीजिंग–काओलून रेल लाइन के बारे में तो चीनी रेल विशेषज्ञों का आज भी कहना है कि यह रेल जितने यात्रियों को एक हफ्ते में ले जाती है, गोरमो–ल्हासा रेलगाड़ी उतने यात्री पूरे साल में भी नहीं ले जा सकेगी।

दूसरी ओर मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया, सिंकियांग, गांसू, गुआंगशी, फुजियान, निंगशिया, युन्नान और चिंघाई जैसे अपने उपनिवेशों और दूर दराज के चीनी इलाकों में 1953 से 1962 के बीच रेलवे लाइन का विकास किया गया। शायद इन रेलमार्गों के बनने के बाद चीन को मिले फायदों का ही परिणाम था कि बीजिंग ने ल्हासा को भी रेलमार्ग से जोड़ने का कदम उठाया। इन इलाकों में जिस तरह से करोड़ों चीनी नागरिकों को बसाने और सिंकियांग तथा भीतरी मंगोलिया जैसे नाजुक उपनिवेशों में सेना की आवाजाही से वहां चीनी नियंत्रण मजबूत हुआ वह तिब्बत रेलमार्ग के बारे में फैसला लेने के लिए काफी था।

1995 में लगाए गए अनुमानों के अनुसार 1118 किमी लंबे गोरमो–ल्हासा रेलमार्ग पर 2.34 अरब डालर खर्च आ रहा था। यानी 10.530 करोड़ रु के बराबर जो अपने किसी भी उपनिवेश में चीन सरकार का आज तक का सबसे बड़ा निवेश है। पैसे के अलावा इस रेलमार्ग के 5000 मीटर ऊंचे, बर्फीले और बहुत कम आक्सीजन वाले इलाकों से होकर गुजरने जैसी समस्याएं भी भारी तकनीकी अड़चन बनी हुई थीं। लेकिन इस सबके बावजूद चीन सरकार द्वारा इस काम को हाथ में लेना यह दिखाता है कि उसके ध्यान में यात्री सेवा से कहीं बड़े इरादे थे। इन इरादों का पहला खुलासा चीन सरकार ने अपनी संसद में तब किया जब इस परियोजना की व्यापारिक उपयोगिता से जुड़े सवालों को यह कहकर रोक दिया गया कि यह एक आर्थिक नहीं बल्कि एक 'राजनीतिक' परियोजना है।

इस परियोजना का राजनीतिक महत्व दुनिया को तब पता चला जब 2001 में गोरमो में रेलमार्ग के निर्माण कार्य का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन उपराष्ट्रपति हू जिंताओ (आजकल राष्ट्रपति) ने घोषणा की कि यह रेलमार्ग तिब्बत को दक्षिण एशिया में चीन की 'दीवार' बनाने का काम करेगा।

लेकिन पिछले दिनों जब भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि तिब्बत में रेलगाड़ी लाने के पीछे चीन का असली इरादा तिब्बत में भारी पैमाने पर सैनिक और सैनिक साजो सामान लाकर तिब्बत को दक्षिणी एशिया की सैनिक छावनी में बदलना और भारत पर अपना सैनिक दबदबा बढ़ाना है तो चीन सरकार की प्रतिक्रिया सुनने लायक थी। इस बारे में बीजिंग में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए चीन सरकार के एक अधिकारी का जवाब था, ''......भारत में कुछ लोग ऐसा मानते दिखते हैं कि इस रेल का इस्तेमाल भारतीय सीमा पर सैनिकों को लाने में किया जायेगा। यह विचार हैरानी भरा है। चीन में किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम तो इसे तिब्बत में आर्थिक विकास के उपकरण तथा पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करने वाली पहल के रूप में देखते हैं।''

इस मामले में चीन के राष्ट्रपति सच बोल रहे हैं या उनका कोई अदना सा अधिकारी, इस विवाद में पड़े बिना अगर पिछले कुछ साल से तिब्बत में खनिजों के बारे में आने वाली खबरों को देखा जाए तो चीनी कहानी का एक तीसरा चेहरा भी दिखने लगता है। इन खबरों के अनुसार नए तिब्बती रेलमार्ग के इलाकों में अचानक तांबे, लोहे, क्रोमियम, हीरे और ऐसे कई खनिजों के विशाल भंडार मिलने शुरू हो गए हैं जिनकी चीन में भारी कमी रही है। चीन के तिब्बती कारनामों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों को अब समझ में आने लगा है कि तिब्बती जनता की यात्रा आसान बनाने और वहां के 'विकास' के लिए बनाए गए इस रेलमार्ग को ऐसे रास्ते से क्यों लाया गया जहां तिब्बती आबादी के सबसे कम और केवल नाममात्र की है।

एक समाचार के अनुसार तिब्बत के यूलोंग में 65 लाख मीट्रिक टन भंडार वाली एक खान मिली है जो पूरे चीन के तांबा भंडारों की कुल क्षमता का दसवां हिस्सा है। चीन की सरकारी खनिज कंपनी आंटेक के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ वान लिंग ने पिछले महीने घोषणा की है कि इस इलाके में नई चीनी टैक्नोलाजी और निवेश बढ़ाकर इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। नए रेलमार्ग से लोहे, क्रोमियम और तांबे जैसे भारी खनिजों को आसानी से भारी मात्रा में चीन भेजा जा सकेगा। इससे पहले लंबे और मुश्किल सड़क मार्ग के कारण यह संभव नहीं था।

उधर तिब्बत के खम प्रांत (अब चीनी युन्नान का हिस्सा) के ल्हुंपो–ला तेल क्षेत्र से रेलमार्ग और गैस पाइपलाइन के रास्ते भारी मात्रा में तेल और गैस तथा खम में पैदा होने वाली पनबिजली को 1984 से चीन भेजा जा रहा है। ठीक यही काम चीन सरकार ने मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया और सिंकियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) में किया है जहां रेलमार्ग के रास्ते करोड़ों हान चीनियों को बसाकर वहां के स्थानीय चरित्र को खत्म किया जा चुका है और वहां के खनिजों और दूसरे प्राकृतिक उत्पादों को ढोकर चीन लाया जा रहा है। मात्र कुछ लाख की आबादी वाले भीतरी मंगोलिया में नए रेलमार्ग के रास्ते से अब तक डेढ़ करोड़ चीनी नागरिक बसाए जा चुके हैं। इससे पहले तिब्बत के खम और आम्दो प्रांतों को तिब्बत से अलग करके उन्हें चीन के युन्नान, सिचुआन, गांज़ी और चिंघाई प्रांतों में मिलाकर और रेल के रास्ते करोड़ों चीनियों को बसाकर उन्हें ठेठ चीनी प्रांतों का रूप दिया जा चुका है।

चीन सरकार ने इन इलाकों में अपने रेलमार्गों की मदद से वहां अपने उपनिवेशी शिकंजे को कसने के लिए बखूबी किया है। 1980 और 90 वाले दशकों में सिंकियांग की मूल मुस्लिम उइगुर जाति के भारी विद्रोहों को कुचलने के लिए बीजिंग सरकार ने जिस तरह से रेल के रास्ते विशालकाय सेना को तैनात किया वह अपने आप में एक उदाहरण है। अब तिब्बत में रेलवे लाइन लाकर वहां की बचीखुची तिब्बती जनता को चीनी नागरिकों के समुद्र में डुबोना और पूरे इलाके पर सैनिक नियंत्रण स्थापित करना चीन के लिए पहले के मुकाबले एकदम आसान हो गया है। इस रेलमार्ग ने चीनी नागरिकों के मन से चीन की दूरी और लंबी–कठिन यात्रा की उस परेशानी को भी दूर कर दिया है जिसकी वजह से वे तिब्बत में बसने के कतराते आ रहे थे। इस रेलमार्ग की मदद से भारत की सीमा तक चीनी सेना और उसके भारी साजोसामान तथा मोबाइल परमाणु मिसाइलों की ढुलाई की क्षमता ने भारत की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाल दिया है।

तिब्बत में रेलगाड़ी लाने के इस चीनी कदम के संदर्भ में 1877 की वह घटना याद करना रोचक होगा जब शंघाई में अंग्रेजों के बनाए रेलमार्ग को चीन के चिंग राजा ने खरीदकर उसे इस कारण उखड़वा दिया था कि अंग्रेजों के विस्तार को रोका जा सके। उसके बाद 1911 में भी सिचुआन में चीनी राजा की रेल योजना के खिलाफ विद्रोह इतना जोर पकड़ गया था कि चिंग साम्राज्य का तख्ता पलट गया।

ऐसे में यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि पिछले पचास साल से तिब्बत की जनता पर हर तरह के जुल्म ढाने वाली और उसे पूरे चीन में सबसे गरीब रखने वाली चीन सरकार को अचानक तिब्बत के 'आर्थिक विकास' की चिंता क्यों सताने लगी है?

–विजय क्रान्ति

तिब्बत में मानवाधिकारों के समर्थन में एक प्रदर्शन : शांतिपूर्ण विरोध

# तिब्बत में मानवाधिकारों की हालत दुनिया में सबसे खराब

## फ्रीडम हाऊस सर्वेक्षण में तिब्बत और चेचन्या को आजादी की निम्नतम '7' रेटिंग मिली, चीन को '6'

*'मुक्त नहीं देश वे हैं जहां जनता के मूल राजनीतिक अधिकार स्थगित रहते हैं और उसके मूल मानवाधिकारों को व्यापक स्तर पर संस्थागत ढंग से नकारा जाता है। वर्ष 2006 में चीन एवं तिब्बत दोनों को ही 'मुक्त नहीं' देशों की श्रेणी में रखा गया है।*

वाशिंगटन, आईसीटी, 19 जनवरी दुनिया भर में स्वतंत्रता के विस्तार एवं समर्थन के लिये कार्यरत गैर सरकारी संगठन 'फ्रीडम हाऊस' ने 2006 के अपने सर्वेक्षण में राजनीतिक अधिकारों एवं मानवाधिकार के लिहाज से तिब्बत को 'बदतर' करार दिया है।

संगठन ने 'दुनिया में आजादी 2007ः दुनिया भर में राजनीतिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों पर एक सर्वेक्षण' को 17 जनवरी को जारी किया। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2006 के दौरान मानवाधिकारों के मामले में तिब्बत दुनिया के 'दो सबसे खराब क्षेत्रों' में से एक रहा। दूसरा चेचन्या है जो रूस के अधीन है। फ्रीडम हाऊस ने अपने सालाना सर्वेक्षण में तिब्बत को विवादास्पद क्षेत्र श्रेणी में रखा है।

इस सर्वेक्षण के स्वतंत्रता संबंधी तुलनात्मक आकलन में तिब्बत को राजनीतिक अधिकारों एवं मानवाधिकार में सात (न्यूनतम आजादी रेटिंग) मिली है। वहीं चीन को भी राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में सात तथा मानवाधिकारों में छह अंक मिले हैं। तिब्बत एवं चीन की रेटिंग गत साल जारी सर्वेक्षण के समान ही है।

इस सर्वेक्षण के अनुसार 2006 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता की स्थिति में 2005 की तुलना में मामूली गिरावट देखने को मिली। सर्वेक्षण के अनुसार स्वतंत्रता की स्थिति के लिहाज से 33 देशों के स्कोर में गिरावट आई जबकि 18 देशों के स्कोर में सुधार हुआ।

संगठन के वक्तव्य में कहा गया है, ''फ्रीडम हाऊस ने नोट किया है कि रूस, वेनेजुएला, चीन, ईरान एवं जिम्बाब्वे जैसी तानाशाह व्यवस्थाओं में लोकतंत्र स्वतंत्रता में भारी गिरावट आई है। इस कारण गत तीस साल में हुए छोटे मोटे सुधार के भी लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है।''

इसके अनुसार यह हमला लोकतांत्रिक आजादी के विस्तार की वकालत करने वाले मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों एवं आंदोलन को लक्ष्य बनाकर किया जा रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार '2006 में दुनिया में आजादी' के लिहाज से 90 देशों को 'मुक्त' के रूप में षामिल किया गया है जो दुनिया की जनसंख्या के 47 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सर्वेक्षण में 58 देशों को 'आंशिक मुक्त' माना गया है जो दुनिया की जनसंख्या का 30 प्रतिशत हिस्सा है जबकि 45 देशों को 'मुक्त नहीं ' के रूप में चिन्हित किया गया है। यहां दुनिया का 30 प्रतिशत हिस्सा वास करता है जिनमें से आधे केवल चीन में रहते हैं।

फ्रीडम हाऊस के अनुसंधान निदेशक आर्क पुडिंगटन ने इस सर्वेक्षण के साथ जारी एक लेख में चीन के बारे में लिखा है,''चीन ने हालांकि आर्थिक स्तर पर अनेक बदलावों का प्रदर्षन किया है पर राजनीतिक आजादी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सुधार की दिशा में बहुत मामूली काम हुआ है।''

फ्रीडम हाऊस ने कहा है कि गत साल में मीडिया और इंटरनेट पर शिंकजा और कसा गया। इसके अलावा इनकी अगुवाई करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा वकीलों के खिलाफ मुकद्मे बढ़े तथा धर्म को राज्य के नियंत्रण में रखने के प्रयास बढ़े।

सर्वेक्षण में 'मुक्त देश' उस देश को माना जाता है जहां खुली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के व्यापक अवसर हों, महत्वपूर्ण स्वतंत्र मानवाधिकार हों तथा स्वतंत्र मीडिया हो। 'आंशिक मुक्त' देश की श्रेणी में वे देश हैं जहां राजनीतिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों की सीमित आजादी हो। इस तरह के देशों में भ्रष्टाचार, कमजोर कानून, जातीय एवं धार्मिक दबाव रहता है तथा प्रायः सत्ता में किसी एक ही राजनीतिक दल विशेष का बोलबाला देखने को मिलता है।

'मुक्त नहीं देश वे हैं जहां जनता के मूल राजनीतिक अधिकार स्थगित रहते हैं और उसके मूल मानवाधिकारों को व्यापक स्तर पर संस्थागत ढंग से नकारा जाता है। वर्ष 2006 में चीन एवं तिब्बत दोनों को ही ' मुक्त नहीं ' देशों की श्रेणी में रखा गया है।

# लियु यांगदोंग की भारत यात्रा के विरोध में धर्मशाला में प्रदर्शन

## सभी प्रमुख संगठनों ने साझा रैली में भाग लिया

धर्मशाला में एक प्रदर्शन : आज़ादी की ललक

धर्मशाला, 13 जनवरी (फुरबी थिनले )। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट (यूएफडब्ल्यूडी) की प्रमुख लियु यांगदोंग की भारत यात्रा के विरोध में धर्मशाला में रैली निकाली गई। तिब्बत समर्थक छह संगठनों द्वारा निकाली गई यह रैली शहर के मुख्य मेक्लोड गंज चौक से मुख्य मंदिर तक गई। इसमें तिब्बती लोग एवं उनके समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए।

श्रीमती लियु की छह दिन की भारत यात्रा का उद्देश्य हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया लेकिन वे आठ जनवरी से यहां हैं और कल रवाना होंगी। चीन सरकार के इस विभाग का गठन मंगोलिया, तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा जमाने और उन्हें चीन में शामिल करने के लिए किया गया था। इस फ्रंट को इन देशों में चीनी उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा और घिनौना प्रतिनिधि माना जाता है। इस रैली के आयोजकों में तिब्बती महिला संगठन टीडब्ल्यूए, तिब्बत में चीनी जेलों में बंद रह चुके भूतपूर्व राजनीतिक कैदियों के संगठन गू चू सुम, मूवमेंट फार तिब्बत, स्टूडेंट फार फ्री तिब्बत एसएफटी तथा फ्रेंड्स आफ तिब्बत इंडिया शामिल थे। रैली का आयोजन तुरत फुरत फैसले के आधार पर किया गया इसके बावजूद इसमें शामिल लोगों की संख्या काबिले गौर थी।

आयोजकों के अनुसार चीन सरकार का यूएफडब्ल्यूडी, स्वतंत्र तिब्बत पर कुख्यात 17 सूत्री समझौता थोपने के लिये जिम्मेदार है। इसी के आधार पर चीन अब तिब्बत के उदारीकरण का दावा करता है। लेकिन 23 मई 1951 को इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही तिब्बत पर चीन द्वारा जबरन कब्जे का युग शुरू हुआ था। इसके साथ ही तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन, नागरिकों की हत्या और सांस्कृतिक विनाश का सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी चल रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इसी विभाग के माध्यम से धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार के साथ चीन सरकार का सीधा संपर्क स्थापित हुआ। वर्ष 2002 के बाद से दलाई लामा के पांच प्रतिनिधि मंडल विभिन्न चरणों में यूएफडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी यात्रा के दौरान इन प्रतिनिधियों की मुलाकात लियु यांगदोंग से हुई। उसके बाद से वार्ताओं में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। निर्वासित सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि चीन के साथ बातचीत की प्रक्रिया जारी रहे।

दलाई लामा तिब्बत के लिये पूर्ण आजादी के अपने रुख में लचीलापन लाते हुए 80 के दशक से 'उचित स्वायत्तता' की मांग कर रहे हैं। निर्वासित सरकार, तिब्बत से सम्बद्ध मुद्दों को निपटाने की कवायद में जुटी है और उसकी मांग तिब्बतियों को सार्थक एवं स्वीकार्य स्वायत्तता है। लेकिन तिब्बती लोगों एक महत्वपूर्ण वर्ग अब भी पूर्ण आजादी के बहाल होने तक संघर्ष के लिये प्रतिबद्ध है और आजादी का संघर्ष जारी रखे है।

रैली के अवसर पर गू चू सुम मूवमेंट के अध्यक्ष भिक्षु नावांग वोएबर ने कहा, 'हम यूएफडब्ल्यूडी को किसी भी सूरत में उसके उस उद्देश्य में कामयाब नहीं होने देंगे जिसके लिये इसकी स्थापना हुई थी, विशेषकर तिब्बत के मामले में।'' उन्होंने कहा कि ''ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से हम चीन से एकदम अलग हैं और मार्क्सवादी चीन की अपेक्षाओं में तिब्बत के विलय होने का कोई सवाल ही नहीं है।''

चीन में यह फ्रंट विभिन्न राष्ट्रीयताओं में एकता के नाम पर चलाया जाता है। पर इसका असली उद्देश्य चीन की 56 गैर हान राष्ट्रीयताओं पर चीनियों का कब्जा सुनिश्चित करना है। इसी के प्रयासों का नतीजा है कि चीन में शामिल इन 56 राष्ट्रीयताओं का कुल जनसंख्या अनुपात अकेली चीनी (हान) के 92 प्रश के मुकाबले केवल 8 प्रश रह गया है। राष्ट्रीयता के हिसाब से लियु यांगदोंग हान हैं। इस फ्रंट का संचालन हमेशा चीनी हाथों में रहता है।

*यूनाइटेड फ्रंट का असली उद्देश्य चीन की 56 गैर हान राष्ट्रीयताओं पर चीनियों का कब्जा सुनिश्चित करना है। इसी के प्रयासों का नतीजा है कि चीन में शामिल इन 56 राष्ट्रीयताओं का कुल जनसंख्या अनुपात अकेली चीनी (हान) के 92 प्रश के मुकाबले केवल 8 प्रश रह गया है।*

# तिब्बतियों को पारंपरिक बौद्ध त्यौहार न मनाने का निर्देश

## काडर और कर्मचारियों पर कड़ी पाबंदी

*पार्टी सचिव चांग शिंगली ने गत कुछ महीनों में तिब्बत में 'देशभक्तिपूर्ण शिक्षा' को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। चीन की उपनिवेशवादी भाषा में 'देशभक्ति' का अर्थ तिब्बत, शिनजियांग (पूर्वी तुर्किस्तान), मंगोलिया और मंचूरिया जैसे सभी कब्जाए हुए देशों में चीनी शासन के प्रति आस्था पैदा करना है। चांग शिंगली का कहना है कि दलाई लामा और उनके समर्थकों के खिलाफ पार्टी 'कड़ा संघर्ष ' कर रही है।*

वाशिंगटन, 10 जनवरी (आईसीटी) चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत के सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं पार्टी सदस्यों पर दिसंबर में एक महत्वपूर्ण बौद्ध वर्षगांठ मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

इस संबंध में ल्हासा समाचार पत्र में एक आधिकारिक नोटिस भी प्रकाशित किया गया। ल्हासा इवनिंग न्यूज 'ला सा वान बाओ' में 12 दिसंबर को प्रकाशित घोषणा में कहा गया है,''सरकार एवं पार्टी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि कैडर एवं स्टाफ के बड़े वर्ग के प्रबंधन, शिक्षा एवं निर्देशन को मजबूत किया जाये।'' इसके परिणामस्वरूप 'गादेन ङाछो' त्यौहार में शामिल होने या मनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। '

उल्लेखनीय है कि यह त्योहार 14वीं शताब्दी के महान बौद्ध गुरू त्सोंगापा की पुण्यतिथि पर होने वाला वार्षिक आयोजन है। उन्होंने तिब्बती बौद्धधर्म के गेलुगपा मत की स्थापना की थी।

इस प्रतिबंध को तिब्बत स्वायत्तशासी प्रदेश के नये पार्टी सचिव चांग छिंगली के अधीन नये कट्टरवादी राजनीतिक माहौल का संकेत माना जा रहा है। कट्टरवादी छिंगली को वैचारिक बदलाव पर जोर देने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और शायद यही कारण है कि इन निर्देशों को एक समाचार पत्र में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया है।

चीनी भाषा में प्रकाशित इस घोषणा में कहा गया है, ''हर किसी को सरकार एवं पार्टी समिति की जरूरतों को निरंतर ध्यान रखना होगा।'' लेकिन तिब्बत के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की सरकार दावा करती है कि तिब्बतियों को अपने धर्म के पालन की पूरी पूरी आजादी है।

तिब्बती पारंपरिक रूप से त्सोंगापा की पुण्यतिथि के दिन मठों तथा घरों में दीये एवं मोमबत्ती जलाते हैं। उन्होंने 1419 में दसवें तिब्बती माह के 25वें दिन प्राण छोड़े थे।लोग इस दिन श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिये ल्हासा के बारखोर परिक्रमा मार्ग पर एकत्रित होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र होने के कारण राजनीतिक दृष्टि से नाजुक माना जाता है। इसीलिए चीनी प्रशासन इस समारोह को रोकना चाहती है।

इस महत्वपूर्ण वर्षगांठ के आयोजन पर सरकार के प्रतिबंध को तिब्बत के चीनी प्रशासन में दलाई लामा के प्रति बढ़ते विद्वेष के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा इसे व्यापक समाज के साथ साथ विहारों में धार्मिक गतिविधियों पर राजनीतिक नियंत्रण के विस्तार की कवायद भी माना जा सकता है।

तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के पार्टी सचिव चांग शिंगली ने गत कुछ महीनों में तिब्बत में 'देशभक्तिपूर्ण शिक्षा' को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। चीन की उपनिवेशवादी भाषा में 'देशभक्ति' का अर्थ तिब्बत, शिनजियांग (पूर्वी तुर्किस्तान), मंगोलिया और मंचूरिया जैसे सभी कब्जाए हुए देशों में चीनी शासन के प्रति आस्था पैदा करना है। चांग शिंगली का कहना है कि दलाई लामा और उनके समर्थकों के खिलाफ पार्टी 'कड़ा संघर्ष ' कर रही है। यांग चुआंतांग से पार्टी सचिव का कार्यभार संभालने वाले शिंगली इससे पहले 26 मई 2006 को तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव नियुक्त किये गये थे। वे शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के कंमाडर पद पर तैनात थे और यह कंपनी शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र (पूर्वी तुर्किस्तान) में चीनी नागरिकों को बसाने को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा यह कंपनी सीमा सुरक्षा एवं 'स्थिरता' का संरक्षण भी करती है। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान वह आम उइगुर जनता में एक 'कट्टरवादी ' के रूप में चर्चित थे।

तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) में उनके कार्यकाल की शुरुआत से ही तिब्बत में पार्टी के वरिष्ठ नेता 'अलगाववाद – विरोधी आंदोलन तथा धार्मिक मामलों के प्रबंधन' को मजबूत करने की मंशा जताते आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों के लिये त्सोंगापा की पुण्यतिथि पर प्रतिबंधित लगाने की यह पहल ल्हासा, द्रेपुंग, सेरा एवं गंदेन जैसे प्रमुख विहारों में तनाव एवं अशांति के बाद की गई है। नवंबर 2005 में द्रेपुंग के भिक्षुओं ने विहार में चीनी 'देशभक्ति' शिक्षा पर जोर दिये जाने तथा पांच भिक्षुओं के निष्कासन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। इसी सिलसिले में एक भिक्षु नावांग जांगचुब ने आत्महत्या कर ली थी।

द्रेपुंग की घटनायें उसी समय हुईं जबकि संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत (उत्पीड़न) मानफ्रेड नोवाक ल्हासा की यात्रा पर थे। हालांकि डा नोवाक इन घटनाओं के प्रति अनभिज्ञ थे। उल्लेखनीय है कि दलाई लामा के

प्रभाव को कम करने के प्रयास के तहत चीनी प्रशासन कुछ तिब्बतियों में शुगदेन देवता की पूजा को बढ़ावा देता रहा है। ल्हासा में एक अन्य घटना में जुलाई 2006 में पुलिस ने सेरा विहार में प्रार्थना सभा में दखल दिया और प्रधान भिक्षु जेंगचुब ग्यालत्सेन को निष्कासित कर दिया गया। रेडियो फ्री एशिया (18 नवंबर 2006) के अनुसार उन पर एक साल की निगरानी थोप दी गई है।

आईसीटी के उपाध्यक्ष मैरी मर्के ने कहा है, ''तिब्बत में धार्मिक आजादी की बात करने वाली चीन की सरकार के गांदेन ङाछो त्योहार के बारे में ये ताजा दिशा निर्देश तिब्बतियों में उसके प्रति विरोध को और बढ़ायेंगे।''

## तिब्बती लेखिका वोज़ेर रेडियो फ्री एशिया के लिये योगदान करेंगी

आईसीटी, 6 जनवरी तिब्बती लेखिका वोज़ेर अपने विचारों के प्रसार के लिये रेडियो का सहारा लेंगी और रेडियो फ्री एशिया अपनी तिब्बती सेवा में उनका एक कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि वोज़ेर की किताबों पर तिब्बत एवं चीन में प्रतिबंध है तथा इंटरनेट पर उनके ब्लाग को चीन सरकार ने बंद कर दिया है। रेडियो की वेबसाइट के अनुसार उसकी तिब्बती सेवा 'वोज़ेर्ज़ फोरम' नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम में वोज़ेर के तिब्बती धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति के बारे में विषेष लेखों का तिब्बती लिप्यातंरण भी शामिल होगा।

उल्लेखनीय है कि चीनी भाषा में लिखने वाली तिब्बत की इस चर्चित लेखिका की किताबों में कविताओं की एक कविता, तिब्बत नोट्स तथा 'क्लचरल रेवेल्यूशन' पर दो किताबें शामिल हैं। उनकी लेखनी का कुछ अंग्रेजी अनुवाद तिब्बतराइट्सडाटआर्ग पर देखा जा सकता है। उनके ब्लाग्स को चीन सरकार ने जुलाई 2006 में बंद कर दिया था। वोज़ेर ने कहा है कि वे चीन में तिब्बत के प्रति जागरुकता फैलाने के लिये बोलती रहेंगी। रेडियो फ्री एशिया को अगस्त 2006 में एक साक्षात्कार में वोज़ेर ने कहा था, ' हालांकि मेरे ब्लाग्स बंद कर दिये गये हैं लेकिन वे मेरी लेखनी एवं आवाज को बंद नहीं कर सकते। चूंकि मैं चीनी भाषा में लिख रही हूं इसलिए मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग तिब्बती संस्कृति, इतिहास एवं परंपराओं को जानें। मैं चाहती हूं कि चीनी लोग तिब्बती इतिहास, संस्कृति, इतिहास, धर्म एवं परंपराओं की सच्चाई जानें।'

उन्होंने कहा,' मैं एक लेखक हूं और अच्छे लेखक का मुख्य दायित्व सच्चाई को प्रकट करना होता है। एक अच्छा लेखक झूठा नहीं हो सकता। सचाई को बताना अच्छे लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है और यह किसी भी लेखक की सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता है।'

उल्लेखनीय है कि मीडिया पर निगरानी रखने वाले संगठन रिपोर्ट्स विदआउट बॉर्डर ने 31 जुलाई 2006 को इन ब्लाग्स को पुनः खोले जाने के लिए चीन सरकार से अपील की थी।

## तिब्बत के रिकार्ड तापमान ने मौसम परिवर्तन की चिंताएं बढ़ीं

7 जनवरी एएफपी के एक समाचार के अनुसार तिब्बत में तापमान हाल ही के दिनों में रिकार्ड ऊंचाई को छू गया है। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने कहा कि पूर्वी तिब्बत के चाम्दो में शुक्रवार का तापमान 21 . 8 डिग्री सेल्सियस रहा जो 1996 में इसी दिन रिकार्ड किये गये अधिकतम तापमान से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

इस हिमालयी क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों के प्रति पहले ही आगाह कर रहे हैं। संवाद समिति ने कहा है कि पूर्वी तिब्बत में ही देचेन जिले में गुरुवार को तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो 2001 में रिकार्ड उच्चतम तापमान से 2.5 डिग्री से अधिक है।

इस हिमालयी क्षेत्र में मौसमी आंकड़ों का संग्रहण 1970 में शुरू किया गया था। तिब्बत पठार को दुनिया में मौसमी स्थिति के बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है। पीपल्स डेली ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि इस क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे है। समाचार पत्र ने हाल ही के एक भू विज्ञान अध्ययन के हवाले से कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र के ग्लेशियर गत तीस वर्षों से औसतन 131.4 वर्ग किलोमीटर की दर से सिकुड़ रहे हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति और न भी बिगड़ी तो भी मौजूदा दर से ग्लेशियर वाला क्षेत्र 2050 तक एक तिहाई तथा 2090 तक आधा कम हो जायेगा।

यह सर्वेक्षण चीन के एयरो ज्योफिजिकल सर्वे के रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट ने किया है। इसमें रेगिस्तान के विस्तार एवं 'वैटलैंड' में कमी जैसी समस्याओं का भी जिक्र है। एक अन्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कहा गया है कि आने वाले दशकों में चीन में तापमान बढ़ेगा, पानी की कमी की स्थिति बदतर होगी।

*तिब्बत पठार को दुनिया में मौसमी स्थिति के बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है। पीपल्स डेली ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि इस क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे है इसके साथ ही अन्य बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। समाचार पत्र ने हाल ही के एक भू विज्ञान अध्ययन के हवाले से कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र के ग्लेशियर गत तीस वर्षों से औसतन 131 . 4 वर्ग किलोमीटर की दर से सिकुड़ रहे हैं।*

तिब्बत में रेलवे के खिलाफ बीजिंग में विदेशी पर्यटकों का प्रदर्शन : उपनिवेशवाद से जंग

# रेल लाइन ने चीनी उपनिवेशवाद को मजबूत करना शुरू किया

## ह्यूमन राइट वाच ने चिंता जताई

न्यूयार्क, 12 जनवरी तिब्बत में रेलवे लाइन के पहुंचने का असर तिब्बत के उपनिवेशवादी शोषण की गति पर पड़ना शुरू हो गया है। न्यूयार्क स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट वाच ने कहा है कि ल्हासा को जुलाई 2006 में रेल लाइन से चीन के साथ जोड़ने के बाद 'तिब्बतियों में यह चिंता बढ़ी है कि वे चीनी से लाकर बसाए जा रहे चीनी नागरिकों का आर्थिक स्तर पर मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

*मानवाधिकारों की हालत पर नजर रखने वालों का कहना है कि तिब्बत में रेलवे की वजह से जो भी आर्थिक सुधार हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा फायदा चीन से लाकर तिब्बत में बसाए जा रहे चीनी नागरिकों को हो रहा है।*

उधर चीन के भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसंधान अधिकारियों ने भी अचानक ही तिब्बत की नई रेलवे लाइन के आसपास वाले इलाकों से तांबे और लोहे के खनिज भंडारों की खोज के समाचार देने शुरू कर दिए हैं। (विस्तृत रिपोर्ट *'तिब्बत–देश'* के अगले अंक में) रेलवे लाइन के चालू होने के बाद अचानक आने वाले इस समाचारों से वे आशंकाएं अब सच लगने लगी हैं कि रेलवे लाइन के पीछे चीन का असली इरादा तिब्बत में चीनी लोगों को बसाना, अपनी सैनिक पकड़ बढ़ाना और तिब्बत के खनिज भंडारों को लूटना है।

दूसरी ओर चीनी संवाद समिति शिन्हुआ ने तिब्बत के बारे में आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया है कि तिब्बत में रेलवे लाइन के आने का असर वहां की अर्थ व्यवस्था पर पड़ना शुरू हो गया है। शिन्हुआ का कहना है कि इस रेल लाइन के कारण तिब्बत और चीन के बीच संपर्क बहुत मजबूत हो गया है। तिब्बत में सामान की परिवहन लागत में 75 प्रतिशत की कमी आई है और पर्यटन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन मानवाधिकारों की हालत पर नजर रखने वालों का कहना है कि तिब्बत में रेलवे की वजह से जो भी आर्थिक सुधार हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा फायदा चीन से लाकर तिब्बत में बसाए जा रहे चीनी नागरिकों को हो रहा है।

शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव से क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में भी उछाल देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में 606 होटल, 5846 कैटरिंग सेवाएं तथा 4,867 शापिंग केंद्र हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नाथू ला सीमा को जुलाई में खोले जाने का सकारात्मक असर भी क्षेत्र के विकास पर पड़ा है।

चीन की ओर से तिब्बत पर शासन चलाने वाले तिब्बत क्षेत्र के पार्टी सचिव चांग शिंगली ने 2006 के लिये तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के लिये आर्थिक आंकड़े देते हुए कहा है कि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद इस साल 13.2 प्रतिशत बढ़कर 3.7 अरब डालर हो जायेगा। रेलवे आने के बाद यह गति तेज़ होने वाली है।

लेकिन ह्यूमन राइट वाच ने 11 जनवरी को जारी अपनी 'विश्व रिपोर्ट–2007 में इस बात को रेखांकित किया है कि तिब्बत में चीनी रेलवे के शुरू होने के कारण तिब्बती जनता के हितों पर खराब असर पड़ रहा है। संगठन ने तिब्बत के घटनाक्रम का सारांश भी प्रस्तुत किया गया है। चीन में पिछले साल मानवाधिकारों की हालत के बारे में अपने निष्कर्ष में संगठन ने कहा कि ,'चीन पीछे की ओर जा रहा है।'

### इस साल 30 लाख पर्यटकों का लक्ष्य

शिन्हुआ संवाद समिति ने अपने 15 जनवरी के एक समाचार में कहा है कि तिब्बत में रेलवे शुरू होने के बाद इस साल 30 लाख विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों का लक्ष्य रखा गया है। यह संख्या गत वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। तिब्बत ने 2007 में पर्यटन से 43.5 करोड़ अमेरिकी डालर आय अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। गत वर्ष इस क्षेत्र में 24 .5 लाख पर्यटक आये जिनसे 33 . 3 करोड़ डालर की आय हुई। समाचार के अनुसार तिब्बत स्थानीय लोगों के लिये रोजगार बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेगा तथा स्थानीय लोगों को गाइड एवं अन्य स्टाफ के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। तिब्बत में चीनी नागरिकों को लाखों की संख्या में बसाए जाने के बाद अब 'स्थानीय नागरिकों'

का मतलब यहां बसे हुए चीनी नागरिकों से है। इससे पहले चीन सरकार ऐसे सभी तिब्बती युवाओं को गाइड की नौकरी से निकाल चुकी है जिन्होंने अपनी पढ़ाई निर्वासन में दलाई लामा द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में की थी।

## तिब्बत रेलवे का और विस्तार होगा

शिन्हुआ ने 14 जनवरी को ल्हासा से अपने एक अन्य समाचार में बताया कि तिब्बत की रेल लाइन को इस साल राजधानी ल्हासा से आगे बढ़ाकर शिगात्से तक ले जाया जायेगा।

एजेंसी ने क्षेत्रीय विकास एवं सुधार आयोग के निदेशक चिन छिनशुन के हवाले से बताया कि प्रस्तावित नयी लाइन चिंघाई–तिब्बत रेल लाइन की पहली फीडर लाइन होगी। उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिनिधि निकाय को बताया कि सरकार निर्माण कार्य को यथाशीघ्र शुरू करने की कोशिश कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार अगर सबकुछ ठीक चलता रहा तो रेल लाइन के लिये व्यावहार्यता अध्ययन जनवरी तक पूरा कर लिया जायेगा। इसी तरह प्राथमिक डिजाइन मई के आखिर तक तैयार होने की संभावना है। वास्तविक काम एक साल में शुरू हो सकता है।

मौजूदा योजना के तहत इस लाइन के 2010 तक चालू हो जाने की संभावना है। चिंघाई के गोरमो से ल्हासा तक की रेल लाइन की लंबाई 1,956 किलोमीटर है। रेलवे के कारण तिब्बत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और आय भी बढ़ी है। चीन के रेल मंत्री के अनुसार रेलवे ने 11 . 8 लाख यात्रियों तथा 11.6 लाख टन माल का वहन किया।

## रेल से तिब्बती तांबा भंडारों का दोहन

तिब्बत में चीनी रेलवे के पहुंचने के बाद चीन सरकार ने अब अपना वह अभियान भी शुरू कर दिया है जिसे लंबे और मुश्किल सड़क मार्गो की वजह से वह पिछले 50 साल से रोके हुए थी। यह अभियान है तिब्बत के खनिजों पर भारी पैमाने पर चीन के लिए दोहन। अब चीन ने न केवल पहले से खोजे गए खनिजों की खानों के विकास और वहां से खनिजों की ढुलाई की योजनाएं शुरू कर दी हैं बल्कि नए खनिजों को खोजने का काम भी शुरू कर दिया है।

वाल स्ट्रीट जरनल ने बीजिंग से 6 दिसंबर को जारी एक समाचार में बताया कि तांबे की बढ़ती मांग को देखते हुए चीन, तिब्बत के दूरदराज के इलाकों में मौजूद खनिज भंडारों के दोहन की तैयारी कर रहा है। पहले इन भंडारों को पहुंच से अधिक दूर और मुश्किल सड़क मार्ग के कारण चीन ने छोड़ा हुआ था। हिमालय पर्वतमाला के करीब के तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में चीन के कुल धातु भंडारों का दसवां हिस्सा मौजूद है। चीन सरकार तिब्बत के खनिजों के दोहन को चीन के विकास एवं औद्योगिकीकरण के लिये महत्वपूर्ण मानने लगी है और इस दिशा में अब उसने गंभीर प्रयास शुरू कर दिए हैं।

तिब्बत में रेल सुरक्षा जांच में लगे चीनी सैनिक : उपनिवेशवाद का रथ

चिंघाई–तिब्बत रेल मार्ग को गत गर्मियों में खोले जाने के बाद तिब्बत के खनिज भंडारों के चीन के हितों में दोहन में बहुत मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में मौजूदा भंडारों में युलांग परियोजना भी शामिल है जिसे चीन की सबसे बड़ी खदान के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। इसे इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खदान बताया जा रहा है।

चीन की सरकारी अनुसंधान फर्म अंताइके के एक वरिष्ठ विश्लेषक वान लिग ने कहा, ' युलांग तांबे की खदान परिचालन में आने के बाद चीन के लिये बहुत महत्वपूर्ण होगी। ' उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा उत्खनन गतिविधियों में नए निवेश बढ़ने से तिब्बत में तांबे के खनन विकास की और गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं।

तांबे की खपत में 2000 के बाद हुई बढ़ोतरी में चीन का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां तांबे की मांग किस तेजी से बढ़ रही है। इस धातु का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक्ल एवं विनिर्माण उद्योग में मुख्यता होता है।

तिब्बती क्षेत्रों में तांबे के 65 लाख मीट्रिक टन के भंडार होने का अनुमान है जबकि चीन के तांबा भंडारों की कुल क्षमता 6.27 करोड़ मीट्रिक टन है।

*तिब्बत में चीनी रेलवे के पहुंचने के बाद चीन सरकार ने अब अपना वह अभियान भी शुरू कर दिया है जिसे लंबे और मुश्किल सड़क मार्गो की वजह से वह पिछले 50 साल से रोके हुए थी। यह अभियान है तिब्बत के खनिजों पर भारी पैमाने पर चीन के लिए दोहन।*

तिब्बत की कहानी —

1. युवा भारतीय समर्थकों के संगठन फ्रेंड्स ऑफ टिबेट ने 'परिक्रमा' और 'जीजी एग्ज़ाइल
2. चंडीगढ़ के तिब्बती विद्यार्थियों ने बीजिंग–ओलंपिक के खिलाफ जनजागरण के लिए चंडी
3. रूस में रोस्तोव आन डान में भारत के तिब्बती ग्युमेद मठ के भिक्षु कलाकारों ने फरवरी
4. तिब्बत की आजादी के प्रति समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित एक धरने में
5. जंतर मंतर पर तिब्बत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए गांधीवादी डा. महेश यादव
6. वर्ष–2007 को भारत में तिब्बत के समर्थन में सघन अभियान–वर्ष के दिल्ली में श्रीगणेश
7. उपरोक्त कार्यक्रम में सांसद श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, श्री तेंपा सेरिंग, प्रो विजय मलहोत्र
8. नांगपा ला में तिब्बती शरणार्थियों पर चीनी सैनिकों की गोलीबारी में बचकर भारत पहुंचे
9. दलाई लामा के कर्नाटक प्रवास के दौरान पेनोर रिंपोछे और अन्य वरिष्ठ तिब्बती भिक्षु उ
10. बर्लिन फिल्म समारोह के दौरान 'शांति के लिए सिनेमा' में तिब्बत समर्थक हालिवुड अ

— कैमरे की जुबानी

ब्रदर्स' के साथ 'रॉक इन एग्ज़ाइल' संगीत समारोह का नई दिल्ली आयोजन किया।
ोगढ़ से दिल्ली तक साइकिल रैली का आयोजन किया।
के पहले सप्ताह में रंगीन मंडला कलाकृति बनाई।
लेखिका अरुंधति राय और गांधीवादी डा. महेश यादव ने तिब्बती महिलाओं का साथ दिया।
ने अपने खून से लिखे पोस्टर प्रदर्शित किए। मेधा पाटकर भी इसमें शामिल हुईं।
समारोह की अध्यक्षता श्री सत्यप्रकाश मालवीय ने की। मुख्य वक्ता प्रो. ब्रह्म चेलानी थे।
ा, लामा ज़ोत्पा, डा. नंद किशोर त्रिखा, डा. आनंद कुमार और कई वरिष्ठ लोग आए।
शरणार्थी 7 फरवरी के दिन धर्मशाला के रिफ्यूजी रिसेप्शन सेंटर में।
नका अभिनंदन करते हुए।
भिनेता रिचर्ड गेअर और अभिनेत्री शेरोन स्टोन।

*(फ़ोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)*

तिब्बती शरणार्थियों को चीन को सौंपने के बाद नेपाली पुलिसकर्मी : मानवाधिकार उल्लंघन

# शरणार्थियों के प्रति नेपाली व्यवहार में सुधार के संकेत

## नेपाली पुलिस ने शरणार्थियों को भारत जाने की सुविधा बहाल की

*नेपाल में इस तरह बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश करने वाले तिब्बती शरणार्थियों पर भारी नकद जुर्माना किया जाता रहा है। जुर्माना न दे सकने वाले शरणार्थियों को जेल में डाल दिया जाता है। 21 नवंबर को नेपाली आव्रजन विभाग ने चार अन्य तिब्बतियों के समूह को भी भारत जाने में मदद की थी।*

तिब्बती वेब पत्रिका 'फायूल' के अनुसार नेपाल के आव्रजन विभाग ने गत दिसंबर में 13 तिब्बती शरणार्थियों के एक और समूह को नेपाल–भारत सीमा पर पहुंचाया जिससे संकेत मिलता है कि राजनीतिक स्तर पर बदलाव के साथ ही इस देश में शरण की इच्छा से आने वाले नये तिब्बती शरणार्थियों के लिये स्थितियों में सुधार हुआ है।

सिंधुपाल चौक में नेपाल की पुलिस ने इन लोगों को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। एक समूह ने बताया कि गाइड की गलती के कारण वे लोग तिब्बत से निकलते समय रास्ता भटक गये। वे एक नेपाली गांव में पहुंचे जहां 100 से अधिक ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पीटा। ग्रामीणों ने उन्हें मानव तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ समझ लिया था। लेकिन गांव के कुछ बुर्जुगों ने उन्हें तिब्बती शरणार्थी के रूप में पहचान लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हाथ सौंपने से पहले गांव वालो ने इन लोगों को भोजन, आश्रय और चिकित्सकीय मदद दी। इनमें से दो व्यक्तियों के हल्की चोटें आई हैं।

काठमांडो के आव्रजन विभाग ने बिना किसी जुर्माने के इन लोगों को नेपाल–भारत सीमा तक पहुंचाया। उल्लेखनीय है कि नेपाल में इस तरह प्रवेश करने वाले तिब्बती शरणाथ्रियों पर बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल में प्रवेश के आरोप में भारी नकद जुर्माना किया जाता रहा है। जुर्माना न दे सकने वाले शरणार्थियों को जेल में डाल दिया जाता है। 21 नवंबर को नेपाली आव्रजन विभाग ने चार अन्य तिब्बतियों के समूह को भी भारत जाने में मदद की थी।

तिब्बती शरणार्थी केंद्र के निदेशक केलसांग चुंग ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि तिब्बत से भागकर बाहर आने वाले नये तिब्बतियों के लिये नेपाल में परिस्थितियों में काफी सुधार हुआ है।

# यूएनपीओ ने जिग्मे ग्यात्सो मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की

यूएनपीओ, 21 दिसंबर : गैर प्रतिनिधित्व वाले देशों एवं लोगों के संगठन यूएनपीओ के एकतरफा कैद संबंधी कार्यदल डब्ल्यू जी ए जी ने तिब्बती राजनीतिक कैदी जिग्मे ग्यात्सो के मामले में कहा है, ''हम चिंता के साथ कह रहे हैं कि कार्यदल जिग्मे ग्यात्सो के मामले में उनकी स्थिति के बारे में चीनी अधिकारियों द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी के आधार पर विचार कर रहा है। हमारा मानना है कि वह उन तिब्बती कैदियों में से एक हैं जिनसे कार्यदल को द्रापची जेल में नहीं मिलने दिया गया था। ''

उत्पीड़न पर विशेष दूत और रिपोर्टर मानफ्रेड नोवाक ने चुशुल जेल में जिग्मे से मुलाकात की थी। नोवाक की मिशन रपट के अनुसार जिग्मे ने नोवाक को बताया कि, उन्हें 30 मार्च 1996 को अपराध जांच दल ने गिरफ्तार कर लिया और पीटा। इसके बाद ल्हासा म्युनिसिपल इंटरमीडियेट पीपल्स कोर्ट ने 25 नवंबर 1996 को 15 साल की कैद तथा पांच साल तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने की सजा सुनाई।

जिग्मे पर गैर कानूनी संगठनों के साथ सांठ गांठ कर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था।

उन्होंने नोवाक को बताया कि गुत्सा जेल में वह एक साल एक माह रहे और वहां बुरा बर्ताव चरम सीमा पर था। चूंकि उनके साथ के आरोपी व्यक्तियों ने अपराध स्वीकार कर लिया तो उन्होंने भी इसे स्वीकार करने का निर्णय किया। उसके बाद अप्रैल 1997 को उन्हें द्रापची जेल में भेज दिया गया। मार्च 2004 को हुई एक घटना में उन्होंने ''दलाई लामा दीर्घायु हों'' का नारा लगा दिया तो उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। अमानवीय अत्याचार का यह क्रम लंबे समय तक चला और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हस्तक्षेप

पर ही रुका। इसके बाद उनकी सजा में दो साल और बढ़ा दिये गये।

अब इस तरह के समाचार मिल रहे हैं नोवाक से बैठक के बाद जिग्मे को अलग थलग कोठरी में डाल दिया गया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जिग्मे अब 2014 के बाद ही रिहा हो सकेंगे। फाउंडेशन की रपट में कहा गया गया है कि जिग्मे के परिवारजनों से मासिक मुलाकात पर और प्रतिबंध लगा दिये गये हैं और उनका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है।

यूएनपीओ ने उपरोक्त तमाम तथ्यों एवं रपटों के आधार पर सं. राष्ट्र कार्यदल से मांग की है कि वह जिग्मे के मामले में तुरंत हस्तेक्षपात्मक कार्रवाई करे।

## जबरन लापता करने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की संधि

22 दिसंबर, रेडियो वॉयस ऑफ अमेरिका के एक समाचार के अनुसार विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अपने विरोधियों का अपहरण कर उन्हें गुप्त जेलों में छिपा देने या उनकी हत्या कर देने पर रोक लगाने संबंधी एक अंतरराष्ट्रीय संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2006 को सहमति दे दी।

इसके तहत संधि के कार्यान्वयन के लिये एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति ऐसे लापता लोगों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा भी करेगी जिनकी सरकार पुष्टि नहीं कर रही है।

तिब्बत के लिये अंतरराष्ट्रीय अभियान आईसीटी की कार्यकारी निदेशक मेरीबेथ मरके ने इस संधि का स्वागत करते हुए कहा कि पंचेन लामा के लापता होने के मामले में यह संधि महत्वपूर्ण हथियार होगी।

## 'मिस अर्थ' प्रतियोगिता में मिस तिब्बत ने भाग लिया

मिस तिब्बत सेरिंग चुंगताक के मिस अर्थ इंटरनेशनल में शामिल होने पर तिब्बती समुदाय में प्रसन्नता है और वे इसे एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिब्बत को मान्यता के रूप में देखते हैं।

उल्लेखनीय है कि इस साल की 'मिस अर्थ' सौंदर्य प्रतियोगिता फिलीपिंस की राजधानी मनीला में आयोजित हुई। इसका थीम वैश्विक पर्यावरण था। इसमें भाग लेने वाली सुंदरियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिये संदेश दिए और पर्यावरण के लिये चिंता का विषय बने कारणों के बारे में चर्चा में भाग लिया।

लंदन के अखबार इंडीपेंडेंट ने ऐसे एक विषय पर लिखा कि तिब्बत में चिंघाई के पठार हजारों ग्लेशियरों का घर हैं और ये ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। चीनी वैज्ञानिकों के ताजा अनुसंधान दर्शाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी के साथ ही इस पठारी क्षेत्र में स्थित 80 प्रतिशत से अधिक ग्लेशियरों की सिकुड़न में तेजी आयी है। यहां 46,377 ग्लेशियर हैं।

गत 50 वर्ष में तिबबत के चिंघाई तथा इसके साथ के बर्फीले इलाकों में तापमान बढ़ने का पर्यावरण पर गहरा प्रतिकूल असर पड़ा है।

मिस अर्थ प्रतियोगिता में भागीदारी करते हुए चुंगताक को दुनिया का ध्यान इस आकर्षित करने का अवसर मिला। चुंगताक का अन्य प्रतिभागियों के साथ विचार विमर्श भी फलदायी रहा। मिस तिब्बत ने खुलासा किया कि वह और मिस चीन चोउ मइ तिंग अच्छी दोस्त बन गईं और भाषा की बाधा के बावजूद उन्होंने संकेतों की भाषा में बात की। मिस तिब्बत को इस बात का खेद था कि उनकी अधिकतर सह प्रतिभागियों को तिब्बत की स्थिति की जानकारी नहीं थी।

## दलाई लामा ने नये संयुक्त राष्ट्र महासचिव को बधाई दी

धर्मशाला, तिब्बतनेट : तिब्बत के निर्वासित शासक और धार्मिक नेता दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र के नये महासचिव बेन की मून को इस महत्वपूर्ण पद पर निर्वाचित होने के लिये बधाई दी है।

दलाई लामा ने इस संबंध में नौ दिसंबर को मून को बधाई संदेश भेजा। इसमें उन्होंने कहा है, ''यह विशेषकर उत्साहवर्धक है कि इस वैश्विक संगठन के सबसे महत्वपूर्ण पद पर एक बार फिर एक एशियाई का चयन हुआ है।''

दलाई लामा ने मून को नये पद की जिम्मेदारी में सफलता की कामना की है। दलाई लामा ने कहा है, ''सं. रा. के चार्टर में व्यक्त सिद्धांत मानवजाति के लिये प्रेरणा का स्रोत हैं। सं. रा. दुनिया भर में अनेक शांति कार्यों एवं मानवीय प्रयासों में संलग्न रहा है।''

अपने बधाई संदेश में दलाई लामा ने कहा है, ''यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी ओर छोटे एवं अपेक्षाकृत कम ताकत वाले देश सहयोग एवं समर्थन के लिये देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी योग्यता से यह विश्व निकाय भविष्य में और प्रभावी एवं न्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा।''

*अपने बधाई संदेश में दलाई लामा ने कहा है, ''यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी ओर छोटे एवं अपेक्षाकृत कम ताकत वाले देश सहयोग एवं समर्थन के लिये देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी योग्यता से यह विश्व निकाय भविष्य में और प्रभावी एवं न्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा।''*

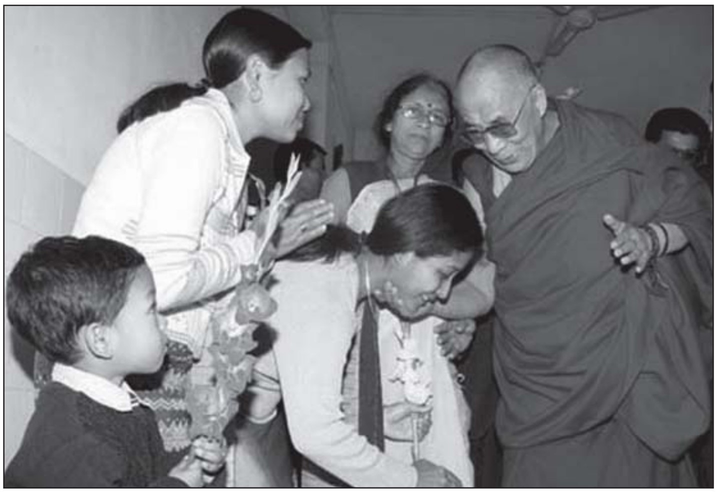

कोलकाता में दलाई लामा का स्वागत करती भारतीय महिलाएं : स्नेह संबंध

# अनौपचारिकता से ही खुशी की शुरुआत होती है : दलाई लामा

## कोलकाता के लोगों से दलाई लामा की मुलाकात

*लेकिन उनके व्यक्तित्व से साक्षात्कार करने के लिये पहली बार यहां आये लोगों के लिये उनके शब्द 'स्वार्थी बनो ' किसी झटके से कम ना थे। उन्होंने कहा,' औरों की सेवा करना अपने हितों को साधने का श्रेष्ठ तरीका है। इसलिए बुद्धिपूर्वक स्वार्थी बनिए।''*

कोलकाता, 15 जनवरी चौदहवें दलाई लामा के लिये कोलकाता आज भी अतिशा और दीपांकर जैसे महान बौद्ध विद्वानों और हावड़ा ब्रिज तथा चिड़ियाघर का शहर है।

तिब्बत के दूरदराज के गांव में पले बढ़े इस तिब्बती शासक ने 1956 में जब पहली बार कोलकाता की यात्रा की थी उस समय वह एक किशोर थे। तब उन्होंने बहुत चाव से यहां के हावड़ा ब्रिज और चिड़ियाघर को देखा था। उनके लिये कोलकाता की तस्वीर सदियों पुरानी इन विरासतों के इर्द गिर्द ही बनी रही है। लेकिन उसके बाद से हावड़ा ब्रिज के नीचे से बहुत पानी बह चुका है और यह शहर चमचमाते माल्स, मल्टीप्लेक्सों एवं आईटी केंद्रों का केंद्र बनता जा रहा है। यह अलग बात है कि इस शहर के प्रति दलाई लामा का विनम्र लगाव आज भी पहले जैसा बना हुआ है।

अपनी इस कोलकाता यात्रा के दौरान अपनी एक सभा में मानव विकास में नैतिकता संबंधी संबोधन की शुरुआत दलाई लामा ने कुछ यूं की, ''अनौपचारिकता से प्रगाढ़ता का आरंभ होता है जो बाद में खुशी की ओर ले जाती है।''

लेकिन उनके व्यक्तित्व से साक्षात्कार करने के लिये पहली बार यहां आये लोगों के लिये उनके शब्द 'स्वार्थी बनो ' किसी झटके से कम ना थे। उन्होंने कहा,' औरों की सेवा करना अपने हितों को साधने का श्रेष्ठ तरीका है। इसलिए बुद्धिपूर्वक स्वार्थी बनिए।''

उन्होंने कहा कि समाज, मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंक है और प्रसन्नता हमारे मन की शांति एवं खुशी से सम्बद्ध है। दयालुता की चर्चा करते हुए नोबल पुरस्कार विजेता ने कहा कि ''अपनी इच्छाओं पर जोर देते समय, हम चाहे अनचाहे प्रतिस्पर्धा एवं वैर में उलझ जाते हैं और जो अंततः हमारी आत्मा एवं दिमाग को विकृतता की ओर ले जाते हैं।''

अपने संबोधन में दलाई लामा ने अनेक विषयों पर खुलकर विचार रखे। श्रोताओं के लिये यह बहुत ही अनूठा अवसर रहा।

## तिब्बत में बढ़ती चीनी जनसंख्या पर दलाई लामा ने चिंता जताई

एएनआई के एक समाचार के अनुसार तिब्बत के निर्वासित शासक और धर्मगुरू दलाई लामा ने तिब्बत में बढ़ती चीनी जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की है।

दलाई लामा यंग मैन्स वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित 'मानव विकास में नैतिकता' विषयक संगोष्ठी में संबोधन के लिये यहां आये हुए थे। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारी जानबूझकर तिब्बत में चीनी नागरिकों को भारी संख्या में बसा रहे हैं और जनसंख्या के अनुपात को चीन के पक्ष में करने में व्यस्त हैं। इन लोगों को वहां विकास के नाम पर भेजा जा रहा है। लेकिन इस खेल के पीछे चीन का असली इरादा तिब्बत में तिब्बती नागरिकों को अर्थहीन अल्पसंख्यक में बदल पर तिब्बत का चीनीकरण करना और तिब्बत समस्या का 'अंतिम हल' निकाल लेना है।

दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत में सार्थक स्वायत्तता तभी हो सकती है जब वहां की जनसंख्या का मूल तिब्बती चरित्र बना रहे।

इसके साथ ही उन्होंने भारत–चीन संबंधों की मजबूती पर भी जोर दिया और कहा कि दोनों देशों एवं समूचे एशिया के विकास के लिये यह जरूरी है कि भारत–चीन संबंध अच्छे हों। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को साझा विश्वास पर आधारित सार्थक दोस्ती बनाने की पहल करनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि तिब्बत मुद्दे के समाधान से ही दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को तिब्बत समस्या के यथाशीघ्र समाधान के लिये प्रयास करने चाहिएं। केवल उसी स्थिति में 'हिंदी चीनी भाई भाई' का विचार सार्थक हो सकेगा।

*कुछ सप्ताह पहले फाउंडेशन फार यूनिवर्सल रिस्पांसिबिलिटी के तत्वावधान में दलाई लामा ने नई दिल्ली में तीन दिन का प्रवचन दिया। सुनने वालों में राजधानी के कई चर्चित लोग भी शामिल थे। इस बारे में टाइम्स आफ इंडिया के सौजन्य से सागरी छाबड़ा का एक आलेख प्रस्तुत है:*

एक प्रार्थना सभा में दीप जलाते हुए दलाई लामा : ज्ञान का प्रकाश

# शत्रु के लिए भी करुणा ज्यादा जरूरी

## फाऊंडेशन फ़ॉर यूनिसर्वल रिस्पांसिबिलिटी के कार्यक्रम में दलाई लामा की सलाह

दलाई लामा पिछले दिनों दिल्ली में थे। अपने एक प्रवचन में उन्होंने एक किस्सा सुनाया, ''मैं एक तिब्बती भिक्षु को लंबे समय से जानता हूं। उन्हें चीनी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एक चीनी कैदखाने में 18 साल तक रखा गया। रिहा होने पर वे अन्य तिब्बतियों के साथ शरणार्थी के रूप में रहने के लिये भारत चले आये।'' दलाई लामा ने धैर्यपूर्वक अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा, 'मैं उनसे मिला और कैद में उनके अनुभव पूछे।'' भिक्षु ने जवाब दिया, ''कई बार ऐसी हालत पैदा हुई जिसमें मेरे लिए काफी गंभीर खतरा हो गया था।'' दलाई लामा ने पूछा, ''किस तरह का खतरा?'' इस पर उनका जवाब था, ''मुझे कभी–कभी ऐसा डर लगने लगता था कि मुझे कैद में रखने वाले चीनियों के प्रति कहीं मैं अपनी करुणा न खो बैठूं।''

यह किस्सा सुनाने के बाद दलाई लामा ने कहा, ''यही तो बुद्ध धर्म है।''

मेरा संगठित धर्म में विश्वास नहीं है लेकिन बौद्ध धर्म की कुछ प्रारंभिक बातें सीखने के लिये मैंने तीन दिन दलाई लामा के सान्निध्य में बिताये। वे क्षण बहुत मूल्यवान थे क्योंकि हम शांति की तलाश के साथ नये साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। दलाई लामा बहुत ही सरल और किसी बालक जैसी हंसी के साथ बात करते हैं। यह हंसी बार–बार उनकी बात का हिस्सा बनती रहती है। वे कहते हैं, ''मैं औपचारिकताओं से थक गया हूं। मैंने बचपन से अब तक इन्हें खूब निभाया है।'' वह तिब्बत के निर्वासित शासक हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म के शीर्ष गुरू हैं। इसके साथ ही वे अहिंसा के उस प्राचीन दर्शन के समर्थक हैं जिसे एक लंगोटी वाले ने 'सत्याग्रह' का नाम दिया था।

अगर आप समझते हैं कि इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनके धार्मिक अनुयायी ही शामिल हुए तो आपको एक बार फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस कार्यशाला में शामिल होने वालों में विदेश सचिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव और फिलहाल भारत–अमेरिका परमाणु समझौते की प्रक्रिया को देख रहे श्याम शरण और नास्काम के अध्यक्ष किरन कार्णिक जैसे लोग भी थे। किसी ने दलाई लामा से सवाल किया, ''आप ऐसे किसी 'दुश्मन' से कैसे निपटते हैं जो वास्तव में आपको कष्ट दे रहा हो?''

दलाई लामा का जवाब था, ''आपका दुश्मन, आपके लिये करुणा का पालन करने का एक माध्यम बन जाता है।'' जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके प्रति करुणा दिखाना बहुत आसान है लेकिन दुश्मन के प्रति करुणा दिखाते हुए आप अपने इस व्यवहार का विस्तार कर सकते हैं। एक ऐसे वैश्वीकरण के इस युग में जहां सफलता (यानी–खरीदने की क्षमता ) को ही असली राह के रूप में चर्चित और मार्केट किया जा रहा है, दलाई लामा ने कई सरल सचाइयों पर बात की। उन्होंने स्वतंत्रता की धारणा और सभी चीजों की मूलभूत एकता की भी बात की।

दलाई लामा ने कहा,''हमारे लिये भी उस मार्ग पर चलना संभव है। लेकिन आपको संपूर्ण सचेतन जगत के प्रति परोपकारिता के साथ करुणा दिखानी होगी जो आपको आंतरिक प्रसन्नता देगी।''

तीन दिन की इस कार्यशाला के अंत में दलाई लामा ने प्रत्येक व्यक्ति को सफेद तिब्बती स्कार्फ और आशीर्वाद दिया। आयोजन की ढेरों फोटो ली गईं लेकिन इनमें विदेश सचिव कहीं नहीं थे। शायद उस फोटो को चीनी सरकार देखना पसंद नहीं करती जो चीन पर अपने कब्जे को और कड़ा कर रही है।

***(लेखक एब फिल्मकार हैं।)***

*दलाई लामा का जवाब था, ''आपका दुश्मन, आपके लिये करुणा का पालन करने का एक माध्यम बन जाता है।'' जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके प्रति करुणा दिखाना बहुत आसान है लेकिन दुश्मन के प्रति करुणा दिखाते हुए आप अपने इस व्यवहार का विस्तार कर सकते हैं।*

चंडीगढ़ साइकिल रैली में तिब्बती युवा : आजादी के मतवाले

# चीन में ओलंपिक के खिलाफ तिब्बती युवाओं की साईकिल रैली

## चंडीगढ़ की तिब्बती युवा कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान

*इस रैली का आयोजन 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक के विरोध में किया गया। रैली के आयोजकों की ओर से जारी वक्तव्य के कहा गया था, ''हम मांग करते हैं कि चीन और तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति में सुधार होने तक आईओसी चीन को ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं दे।''*

चंडीगढ़, 14 जनवरी चंडीगढ़ की क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस (आर टी वाई सी ) ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से नयी दिल्ली तक साइकिल रैली का आयोजन किया जिसमें 40 कार्यकर्ता शामिल हुए। इन 40 लोगों में से 26 साइकिल यात्री थे और बाकी लोग यात्रा मार्ग में व्यवस्था करने वाले सहयोगी यात्री। चार छात्राओं सहित 20 युवा चंडीगढ़ के ही विभिन्न कालेजों से थे।

इस रैली का आयोजन 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक खेलों के विरोध में किया गया। रैली के आयोजन का मकसद भारतीय जनता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओसी के सदस्यों से यह अपील करना था कि वे चीन को इन खेलों के आयोजक का दर्जा देने के फैसले पर फिर से विचार करें। रैली के आयोजकों की ओर से जारी वक्तव्य के कहा गया था, ''हम मांग करते हैं कि तिब्बत एवं चीन में मानवाधिकार की स्थिति में सुधार होने तक आईओसी चीन को ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं दे।''

इस वक्तव्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का जिम्मा चीन को देने के फैसले को इन खेलों की मूल भावना के विपरीत बताया गया है। इसमें कहा गया है कि तमाम दावों एवं वादों के बावजूद चीन एक दलीय तानाशाही वाला राष्ट्र बना हुआ है जहां कानून और न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां कोई स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव नहीं होते, स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव है और मीडिया एवं इंटरनेट पर प्रतिबंध हैं।

साइकिल रैली का रास्ते भर के गांवों और शहरों कस्बों में स्वागत किया गया और उनके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। जगह–जगह रुककर तिब्बती युवाओं ने लोगों को चीनी कब्जे में फंसे हुए तिब्बत की मौजूदा हालत के बारे में बताया। वहां की जनता के खिलाफ चीन सरकार और चीनी सेना द्वारा लगाई गई पाबंदियों और उन पर किए जाने वाले जुल्मों के बारे में भी उन्होंने लोगों को विस्तार से बताया। रास्ते में पड़ने वाले स्कूलों और कालेजों में रुककर भी उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संपर्क किया।

# भारत–चीन सीमा वार्ता पर निर्वासित तिब्बतियों का प्रदर्शन

नयी दिल्ली, 17 जनवरी एएनआई के एक समाचार के अनुसार सीमा विवाद के बारे में चीन के प्रतिनिधि मंडल की भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू होने के अवसर पर निर्वासित तिब्बतियों ने प्रदर्शन किया।

इस दो दिवसीय बातचीत में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन तथा चीन के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई उप विदेश मंत्री दई बिंगो कर रहे हैं।

तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दावा है कि चीन को तिब्बत की भौगोलिक सीमा के बारे में भारत के साथ बात करने का कोई विधि सम्मत या नैतिक अधिकार नहीं बनता है। ऐसी बातचीत में हुआ कोई भी फैसला तिब्बतियों को स्वीकार्य नहीं होगा।

कांग्रेस के सूचना सचिव धोंदुप दोरजी ने कहा,' तिब्बती के रूप में हम जानते हैं कि तथाकथित चीन–भारत सीमा एक भ्रम है। यह ऐसी सीमा है जो 1949 में स्वतंत्र तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद ही अस्तित्व में आई। आम तिब्बती की तरह भारतीय नागरिक भी समझते हैं कि सदियों से यह सीमा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा थी न कि चीन और भारत के बीच।'

ऐसा माना जाता है कि दोनों देशों की यह बातचीत कुछ 'रचनात्मक समाधानों' की तलाश की प्रक्रिया को आगे बढ़ायेगी। दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिये एक 11 सूत्रीय एजेंडे पर 2005 में सहमति जताई थी। यह सहमति प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान बनी थी।

लेकिन इन वार्ताओं में आगे कोई प्रगति नहीं हो सकी और दोनों पक्ष वार्ता की आगामी तारीख भी नहीं तय कर सके। भारत स्थित चीनी राजदूत सुन युक्सी ने अरूणाचलप्रदेश को चीन का क्षेत्र बताकर नया बवाल खड़ा कर दिया था।

चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ की नवंबर 2006 में भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वार्ताओं को गति देने की बात की और उसके बाद इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा चीन के प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर सेबू में मिले तो वार्ताएं इसी सप्ताह करने का फैसला किया गया।

भारत और चीनी कब्जे वाले तिब्बत के बीच 3600 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसमें अरूणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर विवाद है। एक और चीन ने भारत के पूरे अरुणांचल प्रदेश के 'चीनी क्षेत्र' होने का दावा किया है और दूसरी ओर लद्दाख में पाकिस्तान के माध्यम से हथियाए हुए भारतीय इलाके पर वह अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है।

उधर अंग्रेज़ी दैनिक 'द हिंदू' ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है, ''दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने विवाद निपटाने के लिये किसी फ्रेमवर्क के उद्देश्य से अपनी बातचीत जारी रखी। यह बातचीत खुले, दोस्ताना और रचनात्मक माहौल में हुई।''

वक्तव्य में कहा गया है, ''दोनों पक्षों ने अगले दौर की बातचीत चीन में करने पर रजामंदी जताई है। आगामी दौर की बातचीत की तारीख का फैसला दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार किया जायेगा।'' लेकिन इसके साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों में कई दौर की वार्ताओं के बावजूद इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

## भारत चाहता है ल्हासा में वाणिज्य दूतावास खोलना, चीन ने कहा : माफ कीजिए

नई दिल्ली के इंडियन एक्सप्रेस संवाददाता प्रणब ढल सांवत की एक रिपोर्ट के अनुसार ल्हासा में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने के आग्रह को राष्ट्पति हू चिंताओ की हाल ही यात्रा से ठीक पहले चीन ने खारिज कर दिया था।

भारत बार बार यह दोहराता रहा है कि वह तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र को चीनी गणराज्य के हिस्से के रूप में पुष्टि करता है पर इसके बावजूद चीन ने इस आवेदन को खारिज कर दिया।

भारत एवं चीन भूतकाल की घटनाओं का असर द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ने देने की बात करते रहते हैं लेकिन इस घटना से लगता है कि चीन 1962 के भूत को पीछे छोड़ने का इच्छुक नहीं है।

वास्तव में तीन जगहों पर वाणिज्य दूतावास खोलने पर विचार हो रहा था जिनमें ल्हासा, चेंगदू एवं गुआंगचोउ शामिल हैं। चीन ने गुआंगचोउ पर सहमति जता दी जो सिचुआन प्रांत को भी कवर करेगा। चेंग्दू सिचुआन की राजधानी है। इसके बदले में भारत ने कोलकाता में वाणिज्य दूतावास पर सहमति के साथ ही शर्त रखी है कि पूर्वोत्तर के राज्य इस के अधीन नहीं आयेंगे।

ल्हासा के बारे में चीन का कहना है कि फिलहाल वह किसी भी देश को वहां वाणिज्यदूतावास खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। फिलहाल ल्हासा में केवल नेपाल का वाणिज्य दूतावास ही काम कर रहा है जिसकी स्थापना दलाई लामा के 1959 में भारत चले जाने से पहले हुई थी। वर्ष 1962 से पहले भारत का वाणिज्य दूतावास भी ल्हासा में था। लेकिन चीन ने उसके कामकाज में हर तरह के रोड़े अटकाने के बाद उसे बंद कर दिया था। ऐसा लगता है कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र का मामला आने पर चीन अब भी उतना सहज महसूस नहीं करता। शायद यह मामला इस लिहाज से और जटिल हो जाता है कि 1959 में आंदोलन कर रहे तिब्बतियों ने ल्हासा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के समक्ष आवेदन कर औपचारिक रूप से भारत की मदद मांगी थी।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2003 की चीन यात्रा के बाद से ही भारत ने ल्हासा में वाणिज्य दूतावास को पुनः खोलने की इच्छा जतानी शुरू की थी। इसी यात्रा में भारत ने तिब्बत को चीन के एक स्वायत्तशासी प्रदेश के रूप में मान्यता दी थी। भारतीय सूत्रों का कहना है कि इस तरह की पहल से दोनों देशों को कटु अनुभवों को भुलाने में मदद मिलती।

दोनों देशों ने ही सीमा पार संबधं एवं कारोबार को बढ़ावा देने की बात की है। चीन कोलकाता–ल्हासा के व्यापार मार्ग को बहाल करना चाहता है पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इसे खतरनाक मानती हैं। पिछली शताब्दी तिब्बत का अधिकतर कारोबार कोलकाता बेहतर के रास्ते से होता था। नाथू ला–गंगतोक मार्ग के विकास के बाद यह कोलकाता से ल्हासा के बीच यात्रा का उतना ही अच्छा मार्ग होगा जितना कि हाल ही में चीन द्वारा शुरू की गई शिनिंग–ल्हासा रेल।

*ल्हासा के बारे में चीन का कहना है कि फिलहाल वह किसी भी देश को वहां वाणिज्यदूतावास खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। फिलहाल ल्हासा में केवल नेपाल का वाणिज्य दूतावास ही काम कर रहा है जिसकी स्थापना दलाई लामा के 1959 में भारत चले जाने से पहले हुई थी। वर्ष 1962 से पहले भारत का वाणिज्य दूतावास भी ल्हासा में था। लेकिन चीन ने उसके कामकाज में हर तरह के रोड़े अटकाने के बाद उसे बंद कर दिया था।*

ल्हासा–बोधगया साष्टांग यात्रा के दौरान मोतीहारी में ग्यालसेन : आस्था की ताकत

# तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने ल्हासा से बोध गया तक साष्टांग यात्रा की

## कष्टदायी यात्रा में डेढ़ साल लगे

*लामा ने विशेष तैयारी की थी। किसी तरह के शारीरिक नुकसान से बचने के लिये खुद को एक विषेष लबादे में लपेट लिया। इसके अलावा विषेष तरह के जूते एवं दस्तानों का इंतजाम भी किया जिनसे सड़क पर साष्टांग करते हुए खरोंचें न लगें।*

मोतिहारी, बिहार, पांच जनवरी : एएनआई : एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने दुनिया में शांति एवं सद्भाव की प्रार्थना के साथ ल्हासा से बोधगया तक का मार्ग लेटकर साष्टांग करते हुए तय किया।

ग्यालसेन लामा ने दो दोस्तों के साथ यह यात्रा डेढ़ साल पहले ल्हासा से शुरू की थी। बिहार में मोतिहारी पहुंचने पर एएनआई के संवाददाता ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कुछ समय नेपाल में भी बिताया।

लामा ने कहा, ''तिब्बत में मैंने अपनी यात्रा दो दोस्तों के साथ थरगे में चाचा गुंबा मंदिर से शुरू की। मैंने ल्हासा से वीजा लिया और दोस्त सेतान लामा के साथ नेपाल पहुंचा।'' साष्टांग यात्रा में भक्त जमीन पर लेटकर साष्टांग से रास्ते को नापता है। जिस बिंदु पर साष्टांग के दौरान उसका हाथ पहुंचता है उसी बिंदु सक उसका अगला साष्टांग शुरू होता है। ग्यालसेन का यात्रा मार्ग हिमालय के कई कठिन और शून्य से 15–20 डिग्री नीचे वाले इलाकों में से होकर गुजरता है।

इस यात्रा की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लामा ने विशेष तैयारी की थी। किसी तरह के शारीरिक नुकसान से बचने के लिये खुद को एक विषेष लबादे में लपेट लिया। इसके अलावा विशेष तरह के जूते एवं दस्तानों का इंतजाम भी किया जिनसे सड़क पर साष्टांग करते हुए खरोंचें न लगें।

लामा का साथ दे रहे पेमा चोमो ने बताया कि उन्होंने काठमांडो से मोतिहारी तक की अपनी यात्रा को एक माह से कुछ अधिक समय में पूरा किया। उन्होंने कहा, ''हम तिब्बत से आये हैं। वहां से काठमांडो आने में हमें डेढ़ साल लगा।'' उन्होंने कहा कि काठमांडो से बौद्धगया की यात्रा उन्होंने एक माह एवं लगभग एक सप्ताह पहले शुरू की थी।

चोमा ने कहा कि वे यह यात्रा विश्व शांति और सद्भाव के लिये कर रहे हैं। ये लोग दिन में लगभग छह किलोमीटर की दूरी कर रहे हैं और इनके अगले एक या दो माह में अपनी मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद है।


**रजिस्ट्रेशन आफ न्यूजपेपर्ज सेंट्रल रूल्स 1956 के आठवें नियम के अंतर्गत 'तिब्बत देश' के स्वामित्व व अन्य विषयों संबंधी वक्तव्य :–**

1. प्रकाशन का स्थान : 10–एच लाजपत नगर–3, नई दिल्ली–110024
2. प्रकाशन की अवधि : मासिक
3. मुद्रक : जमयांग दोरजी
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : 10–एच लाजपत नगर–3,नई दिल्ली–110024
4. प्रकाशक का नाम : जमयांग दोरजी
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : 10–एच, लाजपत नगर–3, नई दिल्ली – 110024
5. संपादक का नाम : जमयांग दोरजी
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : 10–एच, लाजपत नगर–3, नई दिल्ली – 110024
6. मालिक का नाम : जमयांग दोरजी

मैं, जमयांग दोरजी, यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गयी सूचनाएं मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

जमयांग दोरजी
दिनांक 1 मार्च, 2007
प्रकाशक के हस्ताक्षर